दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/314
तारीख: 17 जुलाई 2026

को

Plexconcil के सभी सदस्य / COA सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: हैंडबुक ऑफ़ प्रोसीजर, 2023 में पैरा 2.50A (इम्पोर्टेड सामान के प्रोडक्शन में ज़बरदस्ती मज़दूरी के इस्तेमाल का पता लगाने का प्रोसेस) को शामिल करना

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना संख्या 21 /2026-27 दिनांक 13 जुलाई 2026

हम यह बताना चाहते हैं कि ऊपर दिया गया पब्लिक नोटिस हैंडबुक ऑफ़ प्रोसीजर्स, 2023 में पैरा 2.50A जोड़ने के बारे में जारी किया गया है, ताकि ज़बरदस्ती मज़दूरी से बनाए गए सामान के इम्पोर्ट का पता लगाने का तरीका बताया जा सके, जो इस तरह है:

पैरा 2.50A: इम्पोर्टेड सामान के प्रोडक्शन में जबरन मज़दूरी के इस्तेमाल के निर्धारण की प्रक्रिया

1. *डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) **अपनी मर्ज़ी से** या भरोसेमंद मटीरियल से सपोर्टेड कोई जानकारी या शिकायत मिलने पर, यह पता लगाने के लिए जांच कर सकता है कि भारत में इम्पोर्ट किया गया कोई भी सामान, पूरी तरह या कुछ हिस्से में, ज़बरदस्ती मज़दूरी का इस्तेमाल करके बनाया गया है या नहीं।*
2. *ऐसी जाँच के प्रयोजनों के लिए, डीजीएफटी आयातक(ओं), निर्यातक(ओं), निर्माता(ओं) या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण से ऐसी जानकारी, दस्तावेज़ या स्पष्टीकरण माँग सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।*
3. *जांच के दौरान, DGFT ज़रूरी समझे जाने पर संबंधित मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों या दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सलाह ले सकता है।*
4. *डीजीएफटी जांच के लिए जहां भी ज़रूरी समझा जाए, किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संगठन, सरकारी अथॉरिटी या एक्सपर्ट बॉडी से जानकारी या टेक्निकल इनपुट भी ले सकता है।*
5. *जांच पूरी होने पर, DGFT एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें जांच के तहत सामान के प्रोडक्शन में ज़बरदस्ती मज़दूरी के इस्तेमाल के बारे में उसके नतीजे होंगे और वह केंद्र सरकार को सही सुझाव दे सकता है, जिसमें फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1992, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2023 के तहत ऐसे सामान के इम्पोर्ट पर रोक लगाने के सुझाव भी शामिल होंगे।*

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां आधिकारिक पब्लिक नोटिस देखें:

https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202607170628 04.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल